ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में चुनौतियां और अवसर

के.सी. चक्रवर्ती

श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग, श्री दिलीप मोदी, अध्यक्ष,एसोचैम, श्री आर.एन. धूत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोचैम, और सांसद, राज्य सभा, श्री जे.एम. गर्ग, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, डॉ. थॉमस मैथ्यू, संयुक्त सचिव, पूंजी बाजार, वित्त मंत्रालय, श्री एम.नरेन्द्र, अध्यक्ष,एसोचैम बैंकिंग और वित्त संबंधी राष्ट्रीय परिषद और अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, श्री टी.एम. भसीन, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, इंडियन बैंक, श्री एम.वी.टंकसाले, कार्यपालक निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, श्री एन शेषाद्रि, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री डी.एस. रावत, महासचिव, एसोचैम, सम्माननीय अतिथिगण, देवियो और सज्जनो। मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे" ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में चुनौतियां और अवसर " विषय पर नेशनल बैंकिंग कॉन्क्लेव में उपस्थित होने का अवसर मिला। जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2007 में ट्रिलियन अमरीकी डॉलर जीडीपी माइलस्टोन तक पहुंच गई और अन्य देशों नामत: अमरीका, यूनाईटेड किंगडम (यूके), जापान, जर्मनी, चीन, फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा, ब्राजील और रूस के साथ ट्रिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गई। वास्तव में 1960 से 1980 के दशक के अंतिम वर्षों तक भारत की जीडीपी अमरीकी डॉलर की दृष्टि से औसतन प्रत्येक 9 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई। तब से दोगुना होने की यह अवधि घटकर लगभग 5 वर्ष हो गई है जो कि संरचनात्मक सुधारों की पहल के साथ हुआ। 2010-11 में वर्तमान बाजार मूल्यों पर भारत की जीडीपी के लगभग 1.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर होने के साथ यह आशा की जा रही है कि 2015-16 तक, अर्थात आगामी बारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान ही भारतीय अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा से आगे निकल जाएगी। इसलिए नीतिनिर्माता और कारोबार में अग्रणी होने के नाते हमें अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए और बहु-ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था (न कि एक ट्रिलियन डालर वाली अर्थव्यवस्था) के प्रबंध में आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

कुछ लोग यह कहते हैं कि भारत विदेशी मुद्रा के भारी अंतर्वाहों के कारण तेजी से बढ़ने वाली विनिमय दर पर आधारित जीडीपी मूल्यन के कारण तेजी से ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया, लेकिन ज्यादातर दूसरे लोग इसे तेजी से आगे बढ़ने की मात्र शुरुआत समझ रहे हैं जिसके चलते आगे चल कर वृद्धि की गति और भी अधिक बढ़ सकती है। पिछले वर्ष मोर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों और अन्य पूर्वानुमानकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि भारत की वृद्धि दर तीन से पांच वर्षों में चीन से भी आगे निकल जाएगी और आने वाले 20 से 25 वर्षों में किसी अन्य बड़े देश की तुलना में तेजी बनी रहेगी। इसलिए मेरा और अन्य लोगों का भी यह मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आने वाले दो तीन दशकों में द्विअंकीय बनी रहेगी।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य का परिदृश्य काफी आशावादी प्रतीत होता है लेकिन चुनौती यह है कि इसे और अधिक समावेशी कैसे बनाया जाए। समानता को बढ़ावा देने वाले वितरण कार्यक्रमों को सरकार द्वारा वित्तीय और अन्य समर्थन प्रदान किये जाने तथा निवेश और वृद्धि में आश्चर्यजनक परिवर्तन के बावजूद प्रारंभिक स्तर पर भारत अभी भी काफी गरीब और कम विकसित देश है। गरीबी के आकलन के लिए योजना आयोग द्वारा 2009 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय गरीबी गणना अनुपात 1993-94 के 45.3 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 में 37.2 प्रतिशत था। प्रथम दृष्ट्या, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण गरीबी में कमी आने की मंद गति बड़ी संख्या में श्रमिकों का अभी भी कृषि पर निर्भर रहना और अशिक्षा अभी भी विकास की संभावना के मार्ग में बाधा हैं, फिर भी इस बात की संभावना है कि इन कमजोरियों को हम पूरी तरह से अपने पक्ष में बदल पाएंगे।

3. वास्तव में ऐसी कई प्रतिकूल बातों को, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्व में झेलनी पड़ी हैं, पहले से ही कम कर लिया गया है तथा उन्हें और अनुकूल बना लिया गया है । उदाहरणार्थ भारत सहित ज्यादातर विकासशील देशों की एक समस्या पूंजी की कमी रही है। इस कमी ने इन अर्थव्यवस्थाओं के निवेश और

*भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा एसोचैम के राष्ट्रीय बैंकिंग सम्मेलन में 17 जून 2011 को नई दिल्ली में दिया गया व्याख्यान। यह व्याख्यान तैयार करने में सुश्री पी.बी. राखी द्वारा दी गई सहायता को साभार स्वीकार किया जाता है।

वृद्धि की संभावनाओं के मार्ग में पूर्व में बाधाएं खड़ी की हैं। लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारत सहित ज्यादातर देशों ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, इसलिए अब पूंजी की कमी की कोई समस्या नहीं है, बल्कि अब प्रश्न यह है कि हम इस पूंजी पर किस दर पर प्रतिफल दे सकते हैं। इसलिए उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में, यदि हम अपेक्षित प्रतिफल देने में समर्थ हैं और अपनी अर्थव्यवस्था में विशेष तौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में पूंजीगत प्रवाहों को आकर्षित कर पाने में समर्थ हैं तो पूंजी की कोई समस्या नहीं है।

4. इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति जीडीपी को बेहतर बनाने के संबंध में कई विकासशील देशों के समक्ष उच्च जनसंख्या वृद्धि भी एक अवरोध थी। तथापि, आर्थिक विकास के नए प्रेरकों के रूप में दक्षता और ज्ञान के उभरकर आने के साथ, उच्च जनसंख्या वृद्धि अवरोध नहीं अपितु एक अवसर बन गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 56.9 प्रतिशत हिस्सा 15-59 आयु वर्ग के लोगों का है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या का केवल 7.5 प्रतिशत हिस्सा "60 वर्ष या उससे अधिक की आयु " वर्ग का है। इससे यह पता चलता है की भारत को अभी वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले तीस वर्षों में भारत में निर्भरता के अनुपात में तेजी से कमी आएगी जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी लाभ की स्थिति होगी। इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले तीस वर्षों के दौरान न केवल भारत की जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति भारत के पक्ष में होगी बल्कि अन्य बीआरआईसी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर होगी।

5. तथापि हमे यह मानना पड़ेगा कि लाभ की ये स्थितियां स्वयं ही उच्च आर्थिक वृद्धि में परिवर्तित नहीं होंगी। इस संबंध में इस अनुकूल जनसांख्यिकीय प्रतिफल से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए, शिक्षा और दक्षता के विकास में निवेश के समुचित प्रयासों की आवश्यकता होगी। 2011-12 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 52,057 करोड़ रुपये आबंटित किया है, जो 2010-11 के शिक्षा व्यय की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर किया गया व्यय, विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है (सारणी)। जी-20 देशों के बीच, भारत के

सारणी: शिक्षा पर व्यय

देश	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय	देश	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय
स्विटज़रलैंड	5.8	दक्षिण अफ्रीका	5.3
यूनाइटेड स्टेट्स	5.7	थाईलैंड	5.2
फ्रांस	5.6	चिली	4.2
यूके	5.3	ब्राज़ील	4.2
मलेशिया	8.1	भारत	4.1
मेक्सिको	5.3	रूस	3.8

टिप्पणी: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सरकार द्वारा किया गया व्यय (2000-2002)
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम

शिक्षा संकेतक न केवल निम्नतम हैं, बल्कि बीआरआईसी देशों और कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली भी बदतर है। 2009 में विश्व बैंक ने यह राय दी की दक्ष लोगों की कमी, विशेषतौर पर सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल साबित हो रही है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार " हमारे देश में संगत आयु वर्ग के लगभग 10 प्रतिशत लोगों ने किसी उच्च शिक्षण संस्थान में अपना नाम लिखा रखा है जबकि ज्यादातर विकसित देशों में यह प्रतिशत 40-50 प्रतिशत के बीच है "। इस प्रयास में बैंक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराकर सुविधाप्रदाता एवं समर्थ बनाने वाले की भूमिका निभाते हैं और उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी है कि कोई भी योग्य छात्र शिक्षा ऋण से वंचित न रह जाए। तथापि, मात्र शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। उद्योग जगत और बैंकों को मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसे छात्रों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और उद्योगों के लिए सही शिक्षा और दक्षता प्राप्त लोग उपलब्ध रहें।

6. हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि हमारे बढ़ते हुए युवा और कार्यशील लोगों का ज्ञान, दक्षता और उत्पादकता ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। इस संबंध में पिरामिड के निचले स्तर पर विकासात्मक और गरीबी उपशमन योजनाओं का न केवल प्रभावकारी क्रियान्वयन आवश्यक होगा अपितु यह भी स्वीकार करने की आवश्यकता होगी कि उत्पादन के नए कारक, नामत: ज्ञान, दक्षता और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था के उत्पादक कारकों के नये द्वार खोल सकते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि उत्पादन के ये नए कारक, जो मानवीय उद्यमशीलता को जमीन, श्रम और पूंजी के कठोर बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, भूमि और श्रमशक्ति की भारी कमी झेलने वाले जापान व इजराइल जैसे देशों सहित, पश्चिमी गोलार्द्ध की ज्ञान आधरित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के

मुख्य प्रेरक हैं। किसी भी उत्पाद/अथवा सेवा के संबंध में समावेशन लाने के लिए प्रौद्योगिकी ही सबसे उचित और सही तरीका है। प्रौद्योगिकी ने उत्पादों और सेवाओं की तेज और कम लागत वाली उपलब्धता सुनिश्चित करके दुनिया भर के सभी उद्योगों में क्रांति ला दी है जिसके चलते ये ऐसे लोगों के लिए भी सुलभ हो गए हैं जो अन्यथा इनका खर्च वहन नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ, व्यावहारिकता और लाभप्रदता भी सुनिश्चित की है। इसके कई अन्य सकारात्मक पहलू भी हैं। यदि प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाकर उत्पादों और सेवाओं की लागत कम की जाती है तो मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। इसके चलते ब्याज दर में भी कमी आएगी जो सतत वृद्धि सुनिश्चित करेगी।

7. पश्चिमी गोलार्द्ध से संकेत लेते हुए भारत को समावेशी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश करनी चाहिए। कृषि आधारित और /अथवा औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में प्रगति ज्ञान पर मालिकाना अधिकार पाने की क्षमता और उसका प्रयोग माल और सेवाओं के सृजन अथवा उन्हें बेहतर बनाने पर आधारित है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में श्रमिक इस रूप में अलग होते हैं कि वे यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, कार्य कैसे किया जाता है और वे कार्य क्यों कर रहे हैं। वे अपने -अपने ज्ञान के क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं और वे अक्सर अपने वरिष्ठ लोगों से बेहतर होते हैं। ज्ञान आधारित श्रमिकों के सम्मान के फलस्वरूप सबसे अधिक अपेक्षित परिणाम प्रबंध में परिवर्तन के रूप में आते हैं क्योंकि इस परिवेश में प्रयोग और नए अविष्कारों को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस तरह हमें अपने नौजवान श्रमिकों को उत्पादकता और वृद्धि के संबंध में सक्षम बनाने के बहुत प्रयास करने चाहिए ।

8. इन लक्ष्यों को गरीबी उपशमन के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अत्यधिक गरीबी और अभाव के कारण गरीब लोग ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं जो सीधे तौर पर उनकी जीविका के लिए तुरंत सहारा नहीं बनते। इसलिए गरीबों को इन पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह अपेक्षित है कि शुरुआत में ही विकासात्मक कार्यक्रमों को लोगों को जीवन यापन करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने और कुछ समय अंतराल पर उनकी आय बढ़ाने पर बल देना चाहिए। इन कार्यक्रमों के बाद लोगों को उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अंतत: जीवन यापन के स्थायी अथवा अस्थायी नुक्सान से बचाव के लिए, प्रभावी तंत्र को इन कार्यक्रमों के पूरक के रूप मे ंकाम करना चाहिए ताकि समावेशी वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

9. वर्तमान में सरकार द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो रोजगार के सृजन पर बल देते हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) ऐसी ही महत्तवपूर्ण पहल है। कई अल्पविकसित तथा गरीब क्षेत्रों में जीवनयापन का सहारा देने में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे महत्त्वपूर्ण कार्यों को छोटा नहीं समझा जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कार्यक्रम बनाए हैं ताकि नियोजित, ढांचागत और सतत वित्तीय समावेशन प्राप्त किया जा सके जैसे कि बिज़नेस कॉरेसपॉन्डेंट और बिज़नेस फैसिलिटेटर माडल, बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन की योजनाएं बनाना, बैंकों से यह अपेक्षा करना कि वे कम से कम चार बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराएं जिनमें ओवरड्राफ्ट सहित नो-फ्रिल खाते शामिल हैं, और रिज़र्व बैंक इन पहलों की व्याप्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

10. समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले एकीकृत और बहुमुखी प्रयास और मानव पूंजी में ईमानदारी से निवेश करना एकमात्र ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ सकते हैं। ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का दूसरा चरण शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के परोक्ष तरीके और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सूचना केंद्रों से संपर्क सूचना की उपलब्धता के लाभ पहुंचा सकते हैं और इसमें किसी विशेष जगह पर निश्चित समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ज्ञान के अर्जन के लाभ दूर के स्थानों से डोमेन ज्ञान की व्यापक उपलब्धता से प्राप्त होते हैं जिससे न्यूनतम लागत से कारोबारी उत्पादकता का स्वरूप बदल सकता हैं। उदाहरणार्थ आईटीसी के ईचौपाल के प्रयोग में उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की संभावना और बाजार मूल्यों के बारे में बेहतर सुविधा की उपलब्धता से कृषि से अधिक लाभ अर्जन की संभावना निहित है। कृषि मंत्रालय की हेल्पलाइन, जिसपर विषय के विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं, भी कृषकों की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में काफी मदद की है। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए

इंटरनेट आधारित ई-शिक्षा पोर्टल असीमित शिक्षा प्रदान करते हैं। ये पोर्टल विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर परोक्ष कक्षाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं और इनकी सीमा किसी निश्चित स्थान पर उपलब्ध कक्षाओं की तुलना में बहुत व्यापक होती है।

11. की जा रही पहलों की तारीफ की जानी चाहिए फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार की आवश्यकता है जिसे नई सहस्राब्दी की शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाया जाना चाहिए। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में शिक्षा संबंधी इनपुटों की प्रभावी उपलब्धता के संबंध में काफी अधिक मात्रा और गुणवत्ता की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, प्राथमिक शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने काफी हद तक विद्यालयों तक पहुंच और बड़ी संख्या में नामांकन के अनुपात में वृद्धि करके शिक्षा के सार्वभौमीकरण में मदद की। फिर भी शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ विद्यालयों में नामांकनों को बढ़ाने की काफी आवश्यकता है। ऐसा निवेश प्रतिफल को बढ़ाने में काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। इस संबंध में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को अधिनियमित करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-ए के लागू करने से बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाले एवं विद्यालय में दाखिला न लेने वालों, शिक्षा की गुणवत्ता और अल्पावधि एवं दीर्घावधि के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों का समाधान हो सकेगा। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारित करने और ज्ञान के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिषद की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

12. इसके अतिरिक्त एक अन्य समस्या है शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा के बीच कोई सामन्जस्य न होना। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउन्डेशन (2010) द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार भारत में 2008 के दौरान इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यह वृद्धि चीन में 9.9 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 5.9 प्रतिशत, यूके में 3.9 प्रतिशत और अमरीका में -1.0 प्रतिशत थी। तथापि, भारत में तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद लगभग 30 प्रतिशत स्नातक अपनी पढ़ाई पूरी करने के एक वर्ष बाद भी बेरोजगार ही रहते हैं। 2005 में मैक-किन्से नासकॉम के अध्ययन ने यह दर्शाया कि भारत के केवल एक चौथाई इंजीनियरिंग स्नातक और महाविद्यालयों के 10-15 प्रतिशत सामान्य स्नातक विदेशों में आईटी और बीपीओ उद्योग में रोजगार पाने के योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त नासकॉम का ऐसा अनुमान है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था उत्तीर्ण होने योग्य प्रत्येक स्नातक के पीछे नौ आर्द्ध-शिक्षित स्नातक पैदा करती है जो शिक्षा के निम्न स्तर को दर्शाता है। तथापि, यदि हम शिक्षा की गुणवत्ता को छोड़ भी दें तो जब हम प्रति मिलियन लोगों में इंजीनियरों की संख्या की बात करते हैं तो भारत के पास मात्र 214, दक्षिण कोरिया के पास सबसे अधिक संख्या 1,435, जापान के पास प्रति मिलियन लोगों में इंजीनियरों की संख्या 765 है और चीन के पास यह संख्या 340 है। शोध में यह भी पता चला कि देश में डॉक्टरेट डिग्री धारकों का प्रतिशत इंजीनियरिंग डिग्री धारकों का मात्र 1 प्रतिशत है। इंजीनियरिंग डिग्री धारकों की तुलना में डॉक्टरेट डिग्री धारकों का प्रतिशत ज्यादातर देशों में कहीं अधिक है, उदाहरणार्थ यूएस में 9 प्रतिशत, यूके में 10 प्रतिशत, जर्मनी में 8 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 3 प्रतिशत। दुनिया के जानेमाने संस्थानों से भारतीय संस्थानों की तुलना करने पर पता चला कि भारत में ज्यादातर संस्थान स्नातक से पूर्व की पढ़ाई से स्नातक शिक्षा तक ही सीमित रह गए हैं और प्रगति करके तथा शोध संस्थानों का रूप नहीं ले पाए हैं । इसलिए स्पष्ट रूप से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए हमें संख्या और गुणवत्ता में काफी सुधार लाना होगा और साथ ही अपने युवाओं के लिए उचित और उत्पादक रोजगार का भी सृजन करना होगा। समावेशी विकास कार्यक्रम को लागू करने के अलावा शिक्षा में निजी क्षेत्र के साथ सरकार द्वारा काफी मात्रा में निवेश की भी आवश्यकता है जिनका लक्ष्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यावसायिक कौशल का विकास करना होना चाहिए। शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है जिनकी समसामयिक उद्यम में व्यावसायिक प्रासंगिकता है।

13. अंततः ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी वाले वृद्धि के इस नए दौर में, सुशिक्षित कार्मचारियों के बिना अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ा पाना काफी कठिन होगा। शिक्षा और कौशल विकास में पर्याप्त निवेश के बिना हम अपनी बढ़ती हुई युवा जनसंख्या को सुशिक्षित कर्मचारी नहीं बना पाएंगे और इसके भयावह परिणाम होंगे। इसलिए हमें समावेशन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा संबंधी तीन दिशाओं में कार्य करना होगा ताकि भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था और इससे भी परे ले जाया जा सके अन्यथा हम वर्तमान वृद्धि दर को भी कायम नहीं रख पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहां उपस्थित उद्योगों के प्रतिनिधि और बैंकर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सतत वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करेंगे।